

पुराने तापीय विद्युत संयंतरों को बंद करने का सुझाव

प्रलिमिस के लिये:

समारट मीटर नेशनल प्रोग्राम, उदय योजना

मेन्स के लिये:

भारतीय विद्युत क्षेत्र की चुनौतियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी संभावनाएँ और लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्लाइमेट रसिर्च होराइजन (Climate Research Horizon) नामक शोध संस्थान द्वारा जारी एक रपोर्ट के अनुसार, देश के 11 राज्यों में 20 वर्ष से पुराने तापीय विद्युत संयंतरों को बंद करने से सरकार को अगले पाँच वर्षों में 53,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।

प्रमुख बढ़ि:

- शोधकर्ताओं के अनुसार, पुराने संयंतरों बंद करने से सरकार को दो तरीके से लाभ होगा-
 - पुराने तापीय विद्युत संयंतरों से उत्सर्जन कम करने के लिये मरम्मत और अतरिक्त उपकरण के खर्च से मुक्ता
 - नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की कम लागत से होने वाली बचत।
- रपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में COVID-19 महामारी के दौरान विद्युत मांग में आई गरिवट के बीच पुराने कोयला आधारित विद्युत संयंतरों को बंद करने और नरिमाणाधीन संयंतरों के नरिमाण कारबैंग को रोक कर 1.45 लाख करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है।
- COVID-19 महामारी के कारण विद्युत मांग में गरिवट और राजस्व उगाही से जुड़ी समस्याओं के कारण विद्युत वितरण कंपनियों का बकाया बढ़कर 114,733 करोड़ रुपये हो गया है।
- रपोर्ट के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय चुनौतियों को दूर करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा **उदय योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana- UDAY)** जैसे प्रयासों के बाद भी उनकी स्थिति और अधिक बिगड़ती गई है।
- गोरतलब है कि वितरण में भारत में कुल उत्पादित विद्युत का लगभग 53% कोयला आधारित संयंतरों से ही आता है।
- इस विश्लेषण में 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) को शामिल किया गया था।
- गोरतलब है कि पूरे देश में विद्युत वितरण कंपनियों या डिसिकॉम (Discom) द्वारा कुल बकाया राशि का लगभग आधा इन्हीं 11 राज्यों से है।

राज्य	लेगावाट	प्रतिशत
भारत	2,31,456	62.2
कोयला	199,595	53.7
निम्नलिखित	6,360	1.7
गैस	24,992	6.7
तेल	510	0.1
छाइडो (नवीकरणीय)	45,699	12.3
नवीकरणीय	6,780	1.8
आरडीएस* (एमएनआरई)	88,042	23.7
कुल	3,71,977	

विद्युत क्षेत्र की वर्तमान समस्याएँ:

■ वित्तीय चुनौती:

- वर्तमान में देश में अधिशेष विद्युत उत्पादन क्षमता होने के बावजूद भी कई डिस्कॉम वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही हैं।
- विद्युत वितरण कंपनियों को पूर्व निधारति अतारकिं दरों पर अपनी सेवाएँ देनी पड़ती है।
- विद्युत वितरण कंपनियों के लिये अपने ग्राहकों के एक विशेष वर्ग को कम दरों या मुफ्त में विद्युत आपूर्ति की अनिवार्यता कंपनियों की प्रगतिके लिये एक बड़ी बाधा रही है।
- वित्तीय कमी के कारण कई सरकारी संस्थाओं से विद्युत कंपनियों को भुगतान में देरी इस समस्या को और बढ़ा देती है।

■ बजिली चोरी :

- हाल के वर्षों में देश के सभी हसिसों में विद्युत मीटर अनिवार्य किये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है परंतु अभी भी बड़े पैमाने पर बजिली की चोरी और कृषि के लिये मुफ्त बजिली से जुड़ी योजनाएँ आवधियुत क्षेत्र के आरथिक नुकसान का एक बड़ा कारण हैं।

विद्युत क्षेत्र पर COVID-19 का प्रभाव:

- COVID-19 महामारी और इसके प्रसार को रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियों के बंद होने से देश भर में विद्युत की मांग में भारी गिरावट देखी गई है।



आवश्यकता से अधिक ऊर्जा उत्पादन:

- शोधकर्ताओं के अनुसार, कई राज्यों में अनुमान के आधार पर विद्युत संयंतरों की स्थापना की गई है, जो उनकी वास्तविक आवश्यकता से बहुत

- अधिक है।
- अधिशेष विद्युत उत्पादन के कारण कई संयंतरों को 'संयंतर भार घटक' (Plant Load Factor- PLF) से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश के विभिन्न हस्तियों में लगभग 66,000 मेगावाट क्षमता के तापीय विद्युत संयंतरों की स्थापना का कार्य चल रहा है।
- वही 29,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंतरों की स्थापना प्रस्ताव/अनुमति के चरण पर है।

सुझाव:

- पुराने तापीय विद्युत संयंतरों को बंद करने की प्रक्रिया तेज़ करना।
- कोयला आधारित विद्युत संयंतरों के नए प्रस्ताव या शुरूआती चरण के संयंतरों का नियमाण स्थगित करना।
- मध्यस्थिता और बातचीत के माध्यम से डिस्कॉम के लिये नियंत्रित लागत दायतित्वों को कम करना।
- कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत मांग को पूरा करने के लिये सामुदायिक सौर फीडरों की स्थापना को बढ़ावा देना।

लाभ:

- वर्तमान में कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की औसत लागत 4 रुपए प्रति घूनटि है और आमतौर पर इसमें वृद्धि देखने को मिलती है।
- जबकि नए सौर ऊर्जा संयंतरों की बोली 3 रुपए प्रति घूनटि से भी कम ही रही है।
- साथ ही इससे हानिकारक गैसों के उत्सर्जन की समस्या को भी नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होगी।

सरकार के प्रयास:

- केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को अपना बकाया चुकाने के लिये 1 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज जारी करने की तैयारी की जा रही है।
- फरवरी 2020 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने '[राष्ट्रीय संवच्छ वायु कार्यक्रम](#)' (National Clean Air Programme-NCAP) के मापदंडों को पूरा न करने वाले पुराने और प्रदूषणकारी विद्युत संयंतरों को बंद करने का सुझाव दिया था।
- केंद्र सरकार COVID-19 महामारी के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत बजिली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिये [90 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज](#) की घोषणा की गई।
- द्वारा जून, 2020 में विद्युत मंत्रालय द्वारा वास्तविक समय में विद्युत खरीद के लिये '[रायिल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट](#)' (Real Time Electricity Market-RTEM) की शुरूआत की गई।

चुनौतियाँ:

- रपोर्ट के अनुसार, विद्युत संयंतरों को बंद करने से कुछ अल्पकालिक नुकसान (जैसे- करदाताओं की आय की क्षति, सरकारी संयंतरों को उम्मीद से पहले बंद करना आदि) का सामना करना पड़ सकता है।
- परंतु इस कदम से उपभोक्ताओं और विद्युत वितरण कंपनियों को होने वाली बचत पर भी ध्यान दिया जाना चाहयि।
- वर्तमान में देश की कुल ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने के लिये आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा संयंतरों के विकास में बहुत समय और धन लग सकता है, साथ ही सौर ऊर्जा संयंतरों से प्राप्त विद्युत का सुरक्षित भंडारण भी एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह:

- वर्तमान में कृषि और घरेलू क्षेत्र में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और ऊर्जा स्तरों के विकेंद्रीकरण के लिये सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहयि।
- विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया धन की समस्या के साथ इस क्षेत्र के सतत विकास के लिये नियंत्रित देय राशि के स्थान पर अनुबंध और अन्य वित्तीय सुधारों पर विचार किया जाना चाहयि।
- विद्युत उत्पादन में नवीन कियायी तकनीकों को अपनाने के साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये नज़िरी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहयि।
- करोस सब्सिडी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिये 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (DBT) और '[स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम](#)' (Smart Meter National Programme-SMNP) जैसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहयि।

स्रोत: द हृदि

